

'अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवायें पहुँचाना हमारी प्राथमिकता'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में अधिकारियों को निर्देश दिये

जयपुर, 19 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हम अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आमजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी राज्य सरकार की सभी बजटीय घोषणाओं को प्रभावी कार्ययोजना के साथ त्वरित गति से पूरा किया जाए, जिससे 'आपणो स्वास्थ्य राजस्थान' की संकल्पना साकार हो।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 48 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मिशन मोड पर चल रही है तथा अब तक लगभग 8 हजार पदों पर नियुक्तिवादी दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे शहरों और कस्बों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में आयुष्मान मॉडल सी.एच.सी. बनाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पीडिआरडी पैकेज शामिल करने, कुछ पैकेज की दरों को तर्कसंगत बनाने तथा पोस्टिगिटी सुविधाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना में जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग



मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर तथा मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

■ इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर के साथ सुधांशु पंत, शिखर अग्रवाल, अखिल अरोड़ा, आलोक गुप्ता, गायत्री राठौड़, अम्बरीश कुमार, भारती दीक्षित, प्रियंका गोस्वामी, नेहा गिरी, इकबाल खान, शाहीन अली, रवि प्रकाश माथुर आदि वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

के अधीन संचालित राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, पैरा मेडिकल काउन्सिल सहित अन्य सभी संस्थाओं के कामकाज की नियमित समीक्षा की जाए तथा किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाने पर उचित कार्यवाही की जाए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गायत्री ए. राठौड़ ने चिकित्सा विभाग की

योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नवाचारों की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के कई मानकों में राजस्थान राष्ट्रीय औसत एवं कई बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। राज्य में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में विभाग के प्रयासों से उल्लेखनीय गिरावट आई है। संस्थागत प्रसव के मामले में राजस्थान देश में अग्रणी है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया

उन्मुलन मिशन के तहत स्क्रीनिंग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, शासन सचिव चिकित्सा अम्बरीश कुमार, मिशन निदेशक एन.एच.एम. डॉ. भारती दीक्षित, सी.ई.ओ. स्टेट हेल्थ एग्ज्योरेंस ऐजेंसी प्रियंका गोस्वामी, प्रबंध निदेशक आर.एम.एस.सी. नेहा गिरी, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा इकबाल खान, निदेशक आई.ई.सी. शाहीन अली खान, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

नई दिल्ली के ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

ने कम्पनी के इस दावे को स्वीकार किया कि प्रोजेक्ट टैक्नीकली और वित्तीय रूप से पूरा करने योग्य नहीं है। उसने भी आर्बिट्रेटर के आदेश को कायम रखा और राज्य सरकार को मय ब्याज अपफ्रंट प्रीमियम लौटाने के लिए कहा। हाईकोर्ट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी (पावर) को यह निर्देश भी दिया कि वे पता लगाएं कि किन अफसरों की वजह से सारी गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने 6 दिसम्बर को अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राज्य के एडवोकेट जनरल अनूप रट्टन ने राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है, जिस पर इस माह के अंत तक सुनवाई हो सकती है।

संसद सत्र...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

अलावा, संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के संविधान सदन में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

कैलाश मानसरोवर यात्रा अगले वर्ष से

■ भारत-चीन सीमा पर सामान्य स्थिति की बहाली के बाद दोनों देशों में सीधी उड़ानें भी शुरू होंगी।

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सामान्य स्थिति की बहाली के बाद, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें और अगले वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.सी.) के राजनीतिक ब्युरो के सदस्य तथा विदेश मंत्री वांग यी के बीच जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ब्राजील के रियो डि जनेरियो शहर में मुलाकात के दौरान, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने माना कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। चर्चा भारत-चीन संबंधों में अगले कदमों पर केन्द्रित रही। इस बात पर सहमति हुई कि विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव-

उप मंत्री तंत्र की एक बैठक जल्द ही होगी। दोनों पक्षों के बीच जिन कदमों को उठाने के बारे में चर्चा हुई, उनमें कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया आदान-प्रदान शामिल थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएँ दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और एस.सी.ओ. ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। जी 20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है।

न्यूक्लियर हमले के लिए रूस ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

मिसाइलों की गतिविधियों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि ये हथियार रूस के अन्दरूनी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच सकते थे, जब तक कोई अन्य सैन्य शक्ति सक्षम रूप से इन्हे गाइड ना कर रही हो। इन मिसाइलों का प्रयोग केवल सटीक खूफिया जानकारी और दिशा निर्देशों पर ही आधारित हो सकता है।

रूस के लिए मुश्किल यह है कि

अब यह स्पष्ट नहीं है कि, गिरफ्तारी से बचे बिना पुतिन भारत की यात्रा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि, ऐसा करना भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन होगा। रूस के आक्रामक रुख में अचानक तेजी आने की वजह है अमेरिका के जाने वाले राष्ट्रपति जो बाइडन, जिन्होंने अचानक ही यह निर्णय ले लिया कि अमेरिका द्वारा दिए जा रहे हथियारों का यूक्रेन रूस की धरती पर उपयोग कर सकता है। बाइडन का यह कदम आगामी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के लिए भी संकट का एक कारण बन सकता है। रूस का नया सिद्धांत अब विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा पैदा की गई परिस्थिति से निपटने के लिए किया गया है, जिसमें उन्होंने,

किसी भी अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सके थे, ना ही, चीन की कुछ एक यात्राओं को छोड़कर, किसी विदेशी यात्रा पर जा सके थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया हुआ है। वो दिल्ली जा सके, 20 सप्ति में भाग लेने नहीं जा सके, क्योंकि, जैसे ही वो भारत की धरती पर कदम रखते, वैसे ही अनिवार्य रूप से अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता।

अब यह स्पष्ट नहीं है कि, गिरफ्तारी से बचे बिना पुतिन भारत की यात्रा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि, ऐसा करना भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन होगा। रूस के आक्रामक रुख में अचानक तेजी आने की वजह है अमेरिका के जाने वाले राष्ट्रपति जो बाइडन, जिन्होंने अचानक ही यह निर्णय ले लिया कि अमेरिका द्वारा दिए जा रहे हथियारों का यूक्रेन रूस की धरती पर उपयोग कर सकता है। बाइडन का यह कदम आगामी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के लिए भी संकट का एक कारण बन सकता है। रूस का नया सिद्धांत अब विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा पैदा की गई परिस्थिति से निपटने के लिए किया गया है, जिसमें उन्होंने,

यूक्रेन को अनुमति दी है कि वो अमेरिका की लांज रंग मिसाइल का उपयोग, रूस के अंदरूनी क्षेत्रों में हमले के लिए कर सकता है।

अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी मिसाइल सप्लाई की है, जो रूस के अंदर टारगेट्स तक बना सकती है। नया रूसी सिद्धांत विशेष रूप से, यूक्रेन के अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों के लिए तैयार किया गया है। परमाणु हमले की यह बात नई नहीं है। पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यह बात कहनी शुरू कर दी थी। उस समय पुतिन को उम्मीद थी कि वो अपने यूक्रेन आक्रमण को कुछ हफ्तों में निर्णायक रूप से समाप्त कर देंगे।

लेकिन, पुतिन किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाए और लम्बे-लम्बे रूसी काफिले, जिनमें बखरबंद वाहन व सैनिक थे, यूक्रेनी सेना के सटीक हमलों से तबाह हो गए। तथापि, हाल ही में रूस की सेना को कुछ सफलता मिली है।

यूक्रेन द्वारा अपना बचाव तथा रूस को प्रत्युत्तर संभव नहीं होता यदि उसे अमेरिका तथा कुछ हद तक यूरोपीय यूनियन राष्ट्रों से भारी वित्तीय व सैन्य मदद नहीं मिलती।

बुधवार को ऊर्जा ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, विकास एवं विस्तार की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में ऊर्जा क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में विकास को गति मिलने के साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों का पर्सदीदा डैस्टिनेशन बने।

प्रेमिका की हत्या ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

और उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर नरसी ने गंभीर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि मृतका अपनी मर्जी से उसके साथ रहती थी। जिसे लेकर उसके परिजनों की सहमति नहीं थी।

महाराष्ट्र की पांच सीटों पर लड़े जा रहे हैं ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

चुके हैं, जिनमें सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री तथा जहाजराजी मंत्री पद भी शामिल हैं।

इस सीट पर, आदिपट्ट ठाकरे ने 2019 के अपने पहले ही चुनाव में 89,248 वोट हासिल कर जबरदस्त जीत हासिल की थी तथा अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी एन.सी.पी. के सुरेश माने, जो केवल 21,821 वोट पा सके थे, को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ठाकरे ने कोविड-19, महामारी के दौरान अपनी सेवा समर्पण के फलस्वरूप अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। उन्होंने कोविड-पॉजिटिव मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती किये जाने पर व्यक्तिगत ध्यान एवं तवज्जो दी थी।

हालाँकि एम.एन.एस. का जनाधार अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन सन्दीप देशपांडे स्थानीय मुद्दों, खासतौर से इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं आवासन, पर फोकस के लिये जाना-पहचाना नाम हैं। उनके सीधे सम्पर्क तथा नागरिकों से जुड़े मामलों में उनके सामने, खासतौर से वर्ल्ड के मराठीभाषी मतदाताओं के बीच उन्हें लोकप्रिय बना दिया है।

महाराष्ट्र की दूसरी अति महत्वपूर्ण सीट है, बारामती जहाँ हाल ही के लोकसभा चुनावों से काफ़ी मिलता-जुलता, पवार परिवार की बीच का

'मोदी जी किस तिजोरी से पांच...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

देने के लिए विराड आ रहे हैं। मैंने सोचा कि उन जैसा राष्ट्रीय नेता इतना तुच्छ काम करने के निम्न स्तर तक नहीं उतरेंगा। लेकिन मुझे वो वहाँ दिखाई दिये। मैं चुनाव आयोग से भाजपा तथा तावड़े के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

कांग्रेस ने तावड़े के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ए. आई. सी. सी. की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि चुनाव उपयोग को इस कथित कृत्यों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "नालासोपरा के विधायकों की एक मीटिंग हो रही थी। हम मतदान वाले दिन आदर्श आचार संहिता का खयाल रखने की चर्चा कर रहे थे, वोटिंग मशीन किस तरह सील की जायेगी, तथा अगर आपत्ति करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। मैं वहाँ उन लोगों को यह सब बताने गया था। (बहुजन विकास अघाड़ी) पार्टी कार्यकर्ताओं-अप्या ठाकुर तथा क्षितिज ने समझा कि हम कैसे बंट रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस जांच कर लें, सी. सी. टी. वी. फुटेज ले लें। मैं 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्या ठाकुर और क्षितिज

मुझे जानते हैं, पूरी पार्टी मुझे जानती है। फिर भी, चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करा ले।"

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पूर्णिया चोगुले ने कहा कि इस मामले में दो एफ.आई.आर दर्ज कराई गई हैं।

चोगुले ने मीडिया को बताया, "मामला और बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ता यहाँ विधिमंजिलों पर मौजूद थे। कुछ धनराशि तथा कुछ डायरियाँ यहाँ से बरामद हुई हैं। दो एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं तथा गैर कानूनी रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन को लेकर तीसरी एफ आई आर दर्ज कराई जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है।"

इसी बीच, भाजपा सांसद तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इन आरोपों की निराधार बताया है।

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में, एम. वी. ए. ने एक आखिरी कोशिश के रूप में एक निराधार आरोप लगाया है। विनोद तावड़े हमारे राष्ट्रीय नेता हैं तथा पार्टी के कई कार्यों को देखते हैं। (नालासोपरा) क्षेत्र के उम्मीदवार ने उनसे मीटिंग में उपस्थित होने के लिए कहा था। वे उधक से ही गुजर रहे थे, इसलिए वे सहमत हो गये। ऐसी मीटिंगों का आयोजन पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान-प्रक्रिया

समझाने के लिए किया जाता है। हम जोर देकर कह रहे हैं कि होटल के सी सी टी वी कैमरे तथा आस-पास के क्षेत्र की चैकिंग करा ली जाए। 5 करोड़ र. किसी जेब में तो आ नहीं सकते। अगर कोई इस राशि को लाया होगा, तो वह दिखाई देगा। उन्हें सबूत देने चाहिए, ऐसे निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए।

आत्महत्या का ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

सुझाव मांगे गए हैं और उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। केन्द्र सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइन्स को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल पिछली सुनवाई पर न्याय मित्र की ओर से कहा था कि अदालत के कई आदेशों के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आए है। इसलिए अदालत गाइडलाइन्स बनाकर उनकी प्रभावी क्रियान्विति के लिए सख्ती बरते। इसके अलावा केन्द्र सरकार की ओर भी कहा था कि उन्होंने गाइडलाइन्स बनाकर 16 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को दे दी। इनमें कोचिंग इंस्ट्रुक्चर के लिए कई प्रावधान बनाए हैं और इनकी सख्ती से पालना करवाई जाए।

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल गुडाड़े हैं, जो स्थानीय परिवेश में अपनी गहरी जड़ों तथा अपने जमीनी स्तर के सम्पर्कों के लिये जाने-माने व्यक्ति हैं। वे भाजपा से पैदा हो चुकी अब या वर्तमान शासन प्रशासन से असन्तुष्टि का लाभ मिल सकता है। उन्हें शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सेवाओं तथा भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुई चिन्ताओं से त्रस्त मतदाताओं के समर्थन का लाभ मिल सकता है।

राज्य की पाँचवी महत्वपूर्ण सीट, कोपरी-पंचपखड़ी है। ठाणे जिले के इस सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे का मुकाबला केदार दिघे से है, जो शिन्दे के राजनैतिक गुरु स्व. आनन्द दिघे के भतीजे हैं। आनन्द दिघे शिव सेना के जने-माने नेता थे।

शिन्दे अक्सर आनन्द दिघे का जिक्र करते हुये, उन्हें अपना राजनैतिक मार्गदर्शक बताते हैं। दिघे से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। राष्ट्रीय अवादी विजेता फिल्म निदेशक प्रसाद ओक द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म "धर्मवीर-2" की फायनेंसिंग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

दिघे के जीवन पर आधारित यह फिल्म शिवसेना के इस स्वर्गीय दिग्गज एवं उसकी विरासत से शिन्दे के गहरे जुड़ाव को पूरी तरह उजागर करती है।



RISING RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY



श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

एनर्जी सेक्टर प्री-समिति

Empowering Rajasthan:
Unlocking the State's Energy Potential

दिनांक: 20 नवंबर 2024

कार्यक्रम स्थल: होटल मैरियट, जयपुर

मुख्य अतिथि: माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा









Confederation of Indian Industry